Q. कैबिनेट मिशन योजना क्या है ?

Q. कैबिनेट मिशन योजना के प्रति कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण अलग-अलग क्यों था ?

ब्रिटिश मंत्रियों का मानना था कि मुस्लिम बहुलता वाले प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्तता देकर ही मुस्लिम लीग को सन्तुष्ट किया जा सकता था। प्रान्तों को संघ से अलग हो जाने की बात नहीं। कैबिनेट मिशन का विवादास्पद बिन्दु 'समूहिकरण व्यवस्था' थी जिसके तहत देश के विभिन्न भागों को तीन भागों में समूहीकृत किया गया —

① उत्तर-पश्चिमी भाग
② पूर्वोत्तर भारत
③ शेष संपूर्ण भारत

इन तीनों भागों को अलग-अलग इकाई के रूप में आपस में संगठित हो जाने की व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक समूह अपनी पृथक कार्यपालिका तथा विधायिका रखते हुए कुछ शक्तियों प्रान्तीय सरकारों की प्रतिनियुक्त कर सकते थे। इस प्रकार हिन्दुओं एवं सिक्खों के हितों की रक्षा करते हुए पंजाब सिंध एवं बलुचिस्तान को मिलाकर पश्चिमोत्तर प्रान्त, असम तथा बंगाल को मिलाकर पूर्वोत्तर प्रान्त के रूप में मुसलमानों को पाकिस्तान का विकल्प प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी।

इस योजना का सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इन इकाइयों के वर्गों में शामिल होना प्रान्तों के लिए वैकल्पिक या अपरिहार्य एक अनिवार्यता।

कांग्रेस के अनुसार यह व्यवस्था प्रान्तों के लिए वैकल्पिक थी कि वे किसी समूह में शामिल हो अथवा नहीं यह उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग की सोच थी कि क्षेत्र के राज्यों के लिए उस क्षेत्र के समूह में शामिल होना एक अनिवार्यता थी।

6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान सृजन की मांग को दुहराते हुए कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया। अन्तरिम सरकार की योजना को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने 25 जून 1946 को प्रस्तावित संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लिया। ताकि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जा सके।

अपने निर्णय के अनुरूप कांग्रेस अन्तरिम सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थी लेकिन वायसराय उस प्रकार की व्यवस्था से सहमत नहीं हुए।

इस पर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को दी गई अपनी सहमति को वापस ले लिया। पाकिस्तान निर्माण की माँग को लेकर मुस्लिम लीग ने तत्काल कार्यवाही दिवस के रूप में हिंसक आन्दोलन प्रारंभ कर दिया जो वास्तव में सरकार के विरुद्ध एक विध्वंसकारी आन्दोलन था। मुस्लिम लीग के समर्थकों ने पंजाब तथा बंगाल में हिन्दुओं की धन-माल को अपार क्षति पहुँचायी।

3 सितम्बर 1946 को कांग्रेस द्वारा अन्तरिम सरकार में शामिल हो जाने से मुस्लिम लीग के नेता और अधिक उत्तेजित हो गए। उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने से मना कर दिया इस तरह देश अराजकता तथा अनिश्चितता के भंवर-जाल में फंस गया।